कोई अवधि निश्चित करना चाहते है इन दो व्यक्तियों को लेने के लिये ? और क्या मंत्री महोदय दिल्ली प्रशासन पर ज़ोर डाल कर उन से निवेदन करेंगे कि इन को तुरन्त कहीं न कहीं ऐब्सार्ब किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय: अगर ऐसे ही दुहाई देनी है तो मंत्री महोदय के पास जाकर वे इस हाउस में क्यों दे रहे हैं ?

श्री फूलचन्द वर्मा: माननीय मंत्री महोदय ने मानवीय कारण बतलाया हैं।

श्री डी० पी० यादव: मैं इस का जवाब दे चुका हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा: आप ने मानवीय कारणों से मूल सूची में ले लिया है। लेकिन दिल्ली प्रशासन नही ले रहा है, उस के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री डी० पी यादव: उन के लिये कुछ उपाय किया जायेगा ?

SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : May I know whether there is any proposal before the Government or before the Delhi Administration to take these NDS instructors who have been transferred from other States, under the Delhi Administration ?

SHRI D. P. YADAV : I do not follow the question. I have already said that on compassionate grounds we acceded to the request for the transfer of the two ladies, namely Mrs. Shakuntala Tandon and Mrs. Varsha Mehta, and they are in Delhi and we are trying to absorb them.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्रश्न केवल दिल्ली मे दो अध्यापिकाओं को लेने का नही है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम केन्द्रीय सरकार चलाती थी। उस के अध्यापको और अध्यापिकाओं को राज्य सरकारो की दया पर छोड़ दिया गया। क्या मंत्री महोदय सदन को विश्वास में ले कर यह बतलायेंगे कि उन में से कितनो को अब तक नौकरी पर रखा गया है और कितनो को नही रखा गया है ?

श्री डी० पी० यादव: एन एफ सी और एन डी एम की टोटल संख्या हमारे पास लगभग 6500 की है। लगभग सभी को राज्य सरकारो ने ले लिया है या लेने के प्रोसेस मे हैं। जब केन्द्र ने कहा है कि सारा खर्च हम देंगे, पैसा हम देंगे तब कोई और प्रश्न ही नहीं उठता है। मान लीजिये किसी राज्य ने उन को नही लिया तब किसी न किसी जगह हम उन को स्केल का प्रोटेक्शन दे कर रखेंगे।

श्री मान सिंह भौरा:-पिछले साल इस का जवाब देते हुए मिनिस्टर साहब ने यह आश्वासन दोहराया था कि अगर कोई स्टेट उन को नही लेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन को रिटायरमेंट तक वही फैसिलिटीज देगी। मुझे इत्तला है कि इस के बारे में आप ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। लेकिन पंजाब में अभी भी बहुत से टीचर्स घूमते फिर रहे है। पता नही आप ने स्टेट गवर्नमेंट्स को जो लिखा था उस का क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कितनी स्टेट्स हैं जिन्होंने आप की बात मान ली है और कितनों ने नही मानी।

श्री डी० पी० यादव: प्राय: सभी स्टेट्स ने मान लिया है जो दो चार छिटपुट केसेज है हम उन को पर्स्यू कर रहे है।

Waiting for Allotment of Accommodation in General Pool

*983. SHRI PRABODH CHANDRA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the total number of applications received in each of the categories (from Type I to VIII) for allotment of accommodation in the general pool in Delhi/New Delhi for the allotment year beginning from the 1st September, 1972;

(b) the priority dates (category-wise) upto which quarters from general pool have been allotted as on the 30th April, 1973; and

(c) the number of persons mentioned in (a) above, who are still waiting for allotment of accommodation from the general pool (categorywise) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing the dates upto which applications on restricted basis were invited for allotment of accommodation in the General Pool at Delhi/New Delhi for the allotment year beginning from 1st September, 1972, number of applications received, number of applications pending and dates of priority covered as on the 30th April, 1973.

Type	Date upto which applications were invited			No. of applications received on restricted basis (in case of Ladies Pool, Types VII & VIII upto date)			No. of applications pending			Date of priorities covered		
	General Pool	S.C./S.T. quota	Ladies Pool	General Pool	S.C./S.T. quota	Ladies Pool	General Pool	S.C /S.T. quota	Ladies Pool	General Pool	S.C./S.T. quota	Ladies Pool
1.	2.	2(a)	2(b)	3	3(a)	3(b)	4	4(a)	4(b)	5	5(a)	5(b)
I	31-12-62	31-12-63	upto-date	4127	616	92	3627	595	92	26-11-54	1-12-48	December 1952
II	31-12-57	31-12-60	-do-	6242	907	2648	5964	886	2624	16-10-47	23-9-47	20-8-51
III	31-12-52	—	-do-	3515	—	231	2556	—	227	8-11-45	—	11-4-47
IV	31-12-50	—	-do-	3805	—	105	3375	—	101	1-4-43	—	8-8-52
V	31-12-64	—	-do-	1411	—	15	1348	—	8	4-12-60	—	—
VI	31-12-65	—	-do-	446	—	—	385	—	—	30-4-62	—	—
VII	Upto date	—	—	242	—	—	233	—	—	5-3-73 (for Secretaries) 31-12-65 (for Additional Secretaries)	—	—
VIII	Upto date	—	—	56	—	—	53	—	—	22-5-67		
				19844	1523	3091	17541	1481	3052			

श्री प्रबोध चन्द्र : मै गवर्नमेंट से जानना चाहता हू कि आया यह अमर वाकया है कि 6,000 के करीब ऐसे गवर्नमेंट मुलाजिम हैं जिन को पिछले बीस सालो से रहने के लिए कोई जगह नही मिली, और जो सी क्लास के मुलाजिमो के लिये 2,000 से ज्यादा क्वार्टर थे वह बड़े तबके के मुलाजिमो ने ले लिये है और वह गरीब तबके के लोगों को नही मिले है। इस की वजह क्या है ?

श्री ओम मेहता : यह सही है कि इस वक्त काफी लोग ऐसे है, जैसा मैंने स्टेटमेंट मे बतलाया जिन को बीस साल से ज्यादा हो गये है और उन को मकान नही मिले है। टाइप (1) मे बीस साल से ज्यादा से मकान न पाने वालो की तादाद 84 है, टाइप (2) मे बीस साल से ज्यादा से मकान न पाने वालो की तादाद 246 है, जिन को बाइस सालो से मकान नही मिले है उन की तादाद 68 है। इसी तरह से टाइप (3) और टाइप (4) मे लगभग 6,000 लोग ऐसे है जिन को अभी मकान नही मिल पाये है। लेकिन अभी ऐसा है कि इस वक्त तक जो हमारी सेटिस्फैक्शन है वह 41.5 है और हम कोशिश कर रहे है कि हमे ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके जिस से हम ज्यादा मकान बना सके। अगर ज्यादा मकान होगे तो जो 20 और 22 वर्ष के है उन को भी मकान मिल सकेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : हजारो की तादाद मे ऐसे गवर्नमेंट के मुलाजिम है जिन्होंने गवर्नमेंट से से कर्जा ले कर मकान बनवाए है। अपने मकान उन्होंने महगे भाव पर लोगो को किराये पर दे दिए है और वह उन सरकारी मकानों मे बैठे हुए है जिन को लेने का उन का कोई हक भी नहीं है। तो आया गवर्नमेंट की कोई ऐसी पालिसी है कि जिस अफसर ने गवर्नमेंट से सस्ते इन्टेरेस्ट पर पैसा ले कर मकान बनवा लिया है वह गवर्नमेंट का मकान छोड़ कर अपने मकान में जाय बजाय इस के कि वह गरीब आदमी का हक दबा कर बैठा रहे और अपने मकान को जो गवर्नमेंट के रुपये से बना है, अधिक किराये पर उठा कर उस का फायदा उठाता रहे ?

श्री ओम मेहता : इस वक्त तक तो ऐसी पालिसी नही थी। लेकिन थोड़े दिनों से हम ने इस को रिव्यू करने को सोचा है कि जिन लोगो ने गवर्नमेंट से लोन लिया है या चीप जमीन जिन्होंने ली है, कोआपरेटिव वगैरह से वह अपने मकान में जा कर रहे या गवर्नमेंट के मकानो में रहे। यह रिव्यू किया जा रहा है इन्क्लूडिंग आफिसर्स।

श्री प्रबोध चन्द्र : जिन लोगो ने मकान बनवाए है वह छोटे तबके के नही है, आई सी एस और बडे बड़े अफसर जो तीन-तीन चार-चार हजार रुपया पाते हैं, उन लोगो ने अपने मकान बनाए है और पाच-पाच हजार रुपया किराया लेते है और गवर्नमेंट को 600-700 रुपये देते हैं। तो आया उन बडे आदमियो को भी छेड़ा जायगा या गरीब आदमियो को ही दबाया जायगा ?

SHRI OM MEHTA : The policy is under review. I quite agree with the hon member that this is a pressing problem. We should take a different view on it.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या मत्री महोदय इस बात पर भी विचार करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज को न केवल दिल्ली में बल्कि और जगहो मे भी मकान नही मिल रहे हैं। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर और स्टेट हेडक्वार्टर्स पर स्टेट गवर्नमेंट के क्वार्टर्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज को मिलते है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज को नही मिलते तो उन एम्प्लाईज के लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोच रही है कि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर या स्टेट हेडक्वार्टर्स पर कुछ एकमोडेशन की व्यवस्था की जाय ?

श्री ओम मेहता : कोशिश यही की जा रही है। हम ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और प्लानिंग कमीशन को लिखा है कि 150 करोड़ रुपया दिया जाय ताकि स्टेट कैपिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जहा इस वक्त तक बहुत कम क्वार्टर्स है वहा पर भी कुछ मकान बनाए जा

सकें ताकि आगे पांचवी योजना के आखीर तक जो सेटिस्फैक्शन है वह 40 प्रतिशत उन जगहों में हो जाय।

श्री राम सूरत प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट ने मकान बनवाए हैं विभिन्न जिलों में उन में जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उन को स्थान देने की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या मंत्री महोदय स्टेट गवर्नमेंट को लिखेंगे कि केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उन को भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो मकान बनवाए है उन में जगह दे?

श्री ओम मेहता : अध्यक्ष महोदय हम लिखेंगे तो जरूर लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्यों कि वह कहेंगे कि हम अपने एम्प्लाइज को देंगे, आप के एम्प्लाईज को कैसे दें? हमें उन के लिए बनाना पड़ेगा।

SHRI SAMAR GUHA: Is it a fact that in the Badarpur village in Delhi Municipality limits, a High School has been acquired by the Government for building a factory? If so, was it done with the sanction of the Delhi School authorities? If so, has any alternate site been provided to them?

SHRI OM MEHTA: This has nothing to do with the question. But if a particular school compound has been acquired by Government, we would definitely provide them alternative site.

SHRI SAMAR GUHA: Was it done with the sanction of the Delhi School authorities?

SHRI OM MEHTA: It is an entirely different question. I require notice.

SHRI SAMAR GUHA: The whole premises of a public utility institution has been acquired and it is being demolished for building a factory there. I want to know whether it has been done with the sanction of the Delhi School Board.

MR. SPEAKER: I did not go into the relevancy of his first question. But how is the school coming in between? I am sorry. It is not relevant at all.

SHRI SAMAR GUHA: A Higher Secondary School is existing there. It has been acquired. I want to know if it has been acquired with the sanction of the Delhi School Board. If so, how could they acquire it? Still no alternative site has been provided.

MR. SPEAKER: The original question relates to types I to VIII accommodation. Where is the school here?

SHRI A. P. SHARMA: The DDA has evolved a new scheme to provide housing accommodation to government employees and other people in this great city of Delhi by providing them either land or built-up houses. What is Government proposing to do about the 250 retired government employees who have nowhere to go but who are being forced to vacate their quarters? What is the alternative Government is going to provide them?

SHRI OM MEHTA: They can take advantage of the DDA scheme in which 2 per cent has been reserved for retiring government employees and members of the Legislatures. But they cannot continue in the government quarters.

SHRI A. P. SHARMA: Will they give preference to these people in the 5 per cent?

SHRI OM MEHTA: Yes, for retiring officers there is a separate scheme.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: From the Minister's reply, it appears that Government is a little serious about providing accommodation to the Delhi employees. May I know whether Government feels any urgency to give the same importance and same priority for providing accommodation to the employees in cities like Calcutta, Bombay, Madras etc?

SHRI OM MEHTA: Yes, as I have already said, we are thinking of building

more residential accommodation in Calcutta and other places also.

Agreement with Poland on Co-operation in Marine Fisheries

+

*984. SHRI P. GANGADEB :
SHRI P. M. MEHTA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether India and Poland have signed an agreement on co-operation in Marine Fisheries between the two countries; and

(b) if so, main features of the agreement ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) The Agreement provides for co-operation in selected fisheries sectors as mutually agreed upon. Joint ventures will also be within the scope of co-operation. There is also provision in the Agreement for the Polish Government to provide to India scientific and technical assistance and training to personnel in marine fisheries development.

SHRI P. GANGADEB : Which are the other countries which have expressed their willingness to assist India in building up a modern marine fishery industry and whether some of them have also made proposals for strengthening our fishing fleet ? What is Government's reaction in the matter ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Apart from this agreement with Poland we are having the Indo-Norwegian project for development of fisheries, some training programmes, surveys etc. The Government of India have an open mind on this. Modern fisheries is a highly complicated subject. I hope the hon. Member will also appreciate that there is a security aspect also and the Government has to be careful while entering into collaboration agreements with any party.

SHRI P. GANGADEB : In view of fisheries having great export potential have the Government given any consideration to opening up of modern fisheries in the Orissa coast with collaboration from Poland or other countries who have the know-how and if so, what is the line of thinking of the Government in this matter ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : The hon. Member asks about the development of fisheries in the eastern coast; this is one of the items on which the Government is seized. We are trying to develop fishing harbours in Orissa but it is for the Orissa Government to take some initiative and the Government of India will try to be helpful.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : May I know whether Government has any proposal to modernise fishing in Bengal, south of the Sunderbans area ?

MR. SPEAKER : This is about signing of an agreement between India and Poland.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In the light of acute shortage of fish which is a very valuable protein food in the domestic market of this country and the extra or additional availability of fish which will follow, I presume, from such agreements, may I know whether these extra supplies are going to benefit the domestic consumers at all or they are going to be made available for export purposes only ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Naturally we produce for both export and domestic consumption . . . *(Interruptions)*

SHRI D. D. DESAI : Will the hon. Minister give details of the implementation of the Indo-Polish agreement ? I want to